सीरीज़ 1

बदलते शहर में रोज़गार

जयपुर में पारम्परिक कामों के मज़दूर

खतरा केन्द्र (संचला फॉउन्डेशन)
फरवरी 2007

बदलते शहर में रोज़गार

जयपुर में
पारम्परिक कामों
के मज़दूर

सिरिज़ –1

ख़तरा केन्द्र
(संचल फॉउन्डेशन)

फरवरी 2007

प्रकाशक — खतरा केन्द्र(संचल फाउंडेशन)

सर्वेक्षण — हेमलता पारीक एवं मोहनलाल पारीक

शोध — शशिकान्त, बसब पॉल, हेमलता

लेखन — शशिकान्त

टाईपिंग एवं पेज सेटिंग — कविता जोशी, डी. लीना

कवर पेज — विनोद कोष्टी

स्केज — प्रणव प्रकाश

मुद्रक — लक्ष्मी पेपर सदन एण्ड प्रिंटर्स, रमेश नगर, नई दिल्ली

आर्थिक सहयोग — एक्शन एड इंडिया
फोर्ड फाउन्डेशन

आभार

सर्वप्रथम आभार वयक्त करता है एक्शन एड इंडिया और फोंड फाउन्डेशन का जिन्होनें इस अध्ययन में आर्थिक सहयोग दिया।

आभार वयक्त करता हुँ जयपुर के उन तमाम संगठनो–बजट अध्ययन केन्द्र, सिकोडिकोन, दलित मानव अधिकार मंच, निर्माण मजदुर पंचायत संगम, हलवाई युनियन का जिन्होने जयपुर मे रोजगार की वस्तुस्थिती से अवगत करवाया।

मुख्य रूप से आभार व्यक्त करता हुँ लेबर एजुकेशन एण्ड डेबलपमेंट सोसाइटी, कोमरेड वकार, पी.एल.मेमरोट और प्रदीप भार्गव (आइ.डी.एस) का जिनके मदद के बिना यह अध्ययन सम्भव नही था।

विषय सुची

प्रवेशिका
1

अध्य्यन की ज़रूरत
3

बदलते जयपुर की तस्वीर
4

जयपुर की अर्थव्यवस्था
6

पारम्परिक कामों का इतिहास
9

परम्परागत कामों की वर्तमान स्थिति
10

1 आंकड़ों का विश्लेषण
2 निजी जानकारी
3 पलायन
4 काम की प्रकृति व आर्थिक हालात
5 महीने में काम
6 काम के घंटे
7 मज़दूरी
8 आवास एवं अन्य सुविधाए
9 मज़दूरों की सबसे बड़ी परेशानी

शहर की योजना में पारम्परिक काम करने वाले मज़दूर का स्थान
22

निष्कर्ष
23

प्रवेशिका

उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में बहुत कुछ बदला है। कुछ बदलाव दिख रहे हैं और कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो अदृश्य हैं, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने नहीं है। इन 15 सालों में हुए बदलावों पर नज़र डालें तो हमें दिखाई देता है कि :–

- शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आयी है। लोगों का पलायन शहरो की तरफ बढ़ा है।
- सकल धरेलु उत्पाद में कृषि (प्राइमरी), उत्पादन(सेकण्डरी) क्षेत्र के योगदान में गिरावट आयी है तथा सेवा (टरश्यरी) के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है।
- प्रति इकाई पूंजी पर जितना रोज़गार पैदा होता था अब उसका केवल 20% ही होता है।(बदलते शहर में रोज़गार, ख़तरा केन्द्र)
- नई आर्थिक नीति आने के 7 साल के भीतर दिल्ली में बेरोज़गारों की संख्या लगभग 300% बढ़ी है।(बदलते शहर में रोज़गार, ख़तरा केन्द्र)
- श्रम कानूनों के विनियमन के नाम पर असुरक्षित, अस्थायी एवं कम मज़दूरी पर श्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है।
- इन सब के नतीजतन असंगठित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। 1978 में 89% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में थे। अब 93% इस क्षेत्र में हैं।
- खुली अर्थव्यवस्था के चलते बहुत से देशी उद्योग–धंधे बंद होते जा रहे हैं जिससे बेरोज़गारी फैल रही है और संगठित क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। मुम्बई, अहमदाबाद, और जयपुर में कपड़ा मिलों के बन्द होने से लाखों मज़दूर सड़क पर आ गए। जयपुर शहर में कई परम्परागत धंधे बिल्कुल गायब हो गए हैं – जैसे पीतल की नक्काशी, लाल मिट्टी बनाने का काम इत्यादि। दिल्ली जैसे शहर में 1996 की उद्योगबंदी से लगभग 55,000 श्रमिक और सन 2000 की उद्योगबंदी से हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं।
- पर्यावरण, प्रदूषण एवं विश्व स्तरीय शहर के नाम पर लोगों को उनके घर और धंधे से बेदखल किया जा रहा है। मुम्बई में नवम्बर 2004 से जनवरी 2005 के बीच 90,000 से 94,000 झुग्गी झोपडियों को तोड़ डाला गया। दिल्ली मे यमुना पुश्ता से 27,000 परिवार और लगभग 1 लाख परिवार दिल्ली के विभिन्न भागों से उजाड़ दिए गए। अहमदाबाद मे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर 30,000 परिवारों पर विस्थापन का खौफ छाया हुआ है।

लोगों के उद्योग धंधों पर ख़तरा मंडरा रहा है। रेडी पटरी, तहबाज़ारी का सफाया हा रहा है। रिक्शे बन्द किए जा रहे हैं।

दूसरे बदलाव जो मूलतः शासन व्यवस्था से संबन्धित है, अगर उस पर नज़र डालें तो पाते हैं किः–

- उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को लचीला और पूंजीपतियों के पक्ष में बनाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन और स्पेशल इकोनोमिक ज़ोन कानून (2005) इसी प्रक्रिया में उठाये गये कदम है।
- सरकार की खर्च करने की प्राथमिकताओं में बदलाव आ रहा है। शहर के आधारभूत ढांचे के रख–रखाव और उसके विकास से सरकार अपना हाथ खींच कर निजी क्षेत्र को सौंप रही है। और शहर की बुनियादी सुविधाओं से शहर के ग़रीब तबके को बेदख़ल किया जा रहा है।
- शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए सब्सीडी (छूट) को हटाकर सरकार पूंजी बाज़ार का सहारा ले रही है।
- ये बदलाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर देश के छोटे और मंझोले शहरों पर भी पड़ रहा है। और इस बदलाव की सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है शहरी ग़रीब मज़दूर।इन बदलावों में शहरी ग़रीबों की दशा को समझने की कोशिश है यह अध्ययन।

ख़तरा केन्द्र

लेबर एजुकूशन एंड डेवलपमेंट सोसाईटी

अध्ययन की ज़रूरत

सन् 1996 से दिल्ली के मेहनतकश मज़दूरों - रेड़ी पटरी वाले, रिक्शा चलाने वाले, तिपहिया चालक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले झुग्गियों और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मज़दूरेां के बीच काम करते हुए हम लोगों को यह अहसास हुआ कि शहरी गरीबों को दिल्ली शहर से योजनाबद्ध तरीके से हटाने की साजिश हो रही है – 1996 की उद्योगबंदी, रिक्शा पर प्रतिबंध, यमुना पुश्ता और दिल्ली की अन्य जगहों से झुग्गियों के विस्थापन से हज़ारों मज़दूर बेरोजगार हो गये। इसी बीच हमने देखा मुम्बई, कोलकता, हैदराबाद व चेन्नई में भी वहीं सिलसिला दोहराया जा रहा हैं

सारे शहरों में एक समानता थी। कोर्ट के आदेश, शहरों का सौन्दर्यीकरण व शहरो के पर्यावरण को साफ रखने की आड़ में ये सारे कर्मकांड किए जा रहा हैं। दिल्ली में किए गए अध्ययन में हमने पाया पूरी अर्थव्यवस्थ सेवा की तरफ बढ़ रही है और उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है।

बड़े शहरों में हो रहे इस बदलाव ने हमें भी सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित हैं या छोटे शहरों में भी हो रहे हैं। हमारे इस प्रश्न ने जयपुर में इस अध्ययन को प्रेरित किया।

❑ ❑ ❑

बदलते जयपुर की तस्वीर

1727 में सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई। जयपुर एक नियोजित शहर के रूप में, अपनी खास कलाकृति के कारण जाना जाता है। जयसिंह का जयपुर चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था जिसके अन्दर आने के लिए नौ दरवाज़े थे। शहर के मकान एक ख़ास कलाकृति से बनें थे – राजा का मकान पीला और सार्वजनिक व अन्य लोगों का मकान गुलाबी था। इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। 1734 तक जयपुर एक बाज़ार के रूप में उभरने लगा और इसी दौरान कई बाज़ार स्थापित हुए जिसमें शामिल है जौहरी बाज़ार, सिरेह देवरी बाज़ार, किशनपोल बाज़ार और गनगौरी बाज़ार। सवाई जयसिंह ने इन बाज़ारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारियों को जयपुर में व्यवसाय करने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उन्हें मुफ्त भूमी और करों में छूट दी गई। परिणामस्वरूप जयपुर एक व्यवसायिक केन्द्र के रूप में उभरा और जयपुर की सीमा का और भी अधिक विस्तार हुआ।

1727 से लेकर अब तक जयपुर का कई गुना विस्तार हुआ है। शहर के विस्तार के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1951 में जहां इसकी जनसंख्या 0.3 लाख थी वहीं 2001 में इसकी जनसंख्या 2.3 लाख हो गई। 1971 से 2001 के बीच औसतन वार्षिक बढ़त 4.1% से 4.7% के बीच में है। 1981 में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम थी किन्तु 1991 में 0.6% की गिरावट आई और पुनः 2001 में जनसंख्या 0.2% की दर से बढ़ी। जनसंख्या में वृद्धि कुछ तो प्राकृतिक है और कुछ प्रवास (migration) के कारण।

1991 में जहां प्रवास से जनसंख्या में वृद्धि केवल 29% थी वहीं वह 2001 में घटकर 27% हो गयी। फिर भी प्रवासियों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है। 1991 से 2001 के बीच तकरीबन 2 लाख प्रवासियों की संख्या जुड़ी और प्रवासियों की संख्या 4 लाख से 6 लाख हो गयी।

प्रवास की उत्पत्ति पर नज़र डालें तो पाते हैं कि 1991 में जहां शहर और गांव से आने वाले लोगों की संख्या तकरीबन बराबर थी वहां 2001 में शहर से आने वाले लोगों की संख्या 30.5% से 53.4% हो गयी। वहीं गांव से आने वाले लोगों की संख्या 49.5% से घटकर 46.6% हो गयी। अर्थात दूसरे छोटे शहरों से बेहतर सम्भावनाओं की तलाश में लोग जयपुर का रुख कर रहे हैं। इन प्रवासियों में

1991 तक 70% प्रवासी राजस्थान से थे एवं 30% देश के अन्य भागों से। 2001 में प्रवासियों की जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा 2% गिरकर 68% हो गया और देश के अन्य भागों का हिस्सा 2% से बढ़कर 32% हो गया। इस प्रवास की मुख्य वजह रोज़गार, खासकर वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्र में रोज़गार की बढ़ती सम्भावनाओं को बताया जा रहा है। मास्टर प्लान 2011 के अनुसार प्रवासियों का 36% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता हैं।

❑ ❑ ❑

Map growing city

जयपुर की अर्थव्यवस्था

जयपुर की जनसंख्या की 30% आबादी कामगारों की है। कामगारो के काम का बंटवारे का ट्रेंड बताता है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें 1991 में 31.8% कामगार कार्यरत हैं। उद्योग का स्थान दूसरा है जो 26.1% लोगों को रोज़गार देते है – 3.9% घरेलू उद्योग और 22.2% अन्य उद्योग। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 1961 में 16.47% से बढ़ोत्तरी हो कर 1991 में 23.98% हो गयी वहीं मास्टर प्लान 91 में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 70000 कामगारों का अनुमान लगाया था लेकिन इसकी संख्या 1,02,521 हो गयी। इसमें बढ़ोत्तरी का कारण अनौपचारिक क्षेत्र और दूसरे छोटे दुकानों का खुलना है।

वहीं दूसरी ओर उद्योग में रोज़गार 1961 में 26.50% से घटकर 1991 में 26.10% रह गया।

अनौपचारिक क्षेत्र

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों – व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, कृषि, निर्माण, परिवहन में एक अनौपचारिक क्षेत्र कार्यरत है। 94% कामगार अर्थव्यवस्था के इसी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। जयपुर में अनौपचारिक क्षेत्र में 63% की बढ़ोत्तरी इन 10 सालों में हुई है तथा इसमें से 70% ऐसे रोज़गार हैं जो जयपुर में नए हैं। अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है पर क्या शहर की नीति में इनके लिए कोई स्थान है?

बदलती अर्थव्यवस्था में बदलती नीति

शहर की नीतियों में मास्टर प्लान की अहम भूमिका होती है। मास्टर प्लान शहर का भविष्य तय करती है। इसी सन्दर्भ में अगर हम जयपुर मास्टर प्लान 91 पर एक नज़र डालें तो हमें दिखता है कि मास्टर प्लान 91 में आवासीय क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। भूमि उपयोग योजना में 52% आवासीय क्षेत्र के लिए विकास करना था और 62% विकास हुआ। 5.4% व्यवसायिक क्षेत्र के लिए होना था पर केवल 3.8% हुआ। इसी तरह से 16% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास करना था परन्तु केवल 10% ही विकास किया गया। 3 प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में केवल 1 ही बनाया गया। अर्थात मास्टर प्लान 91 की ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाया तो ज़ाहिर है कि मास्टर प्लान 2011 में योजनाकारों को

उन कमियों को मास्टर प्लान 2011 योजना में शामिल करना चाहिए था। किन्तु 2011 मास्टर प्लान में इन बातों की अनदेखी की गई है। केवल 3% क्षेत्र ही व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है जो व्यवसायिक मांगों से कहीं कम है। इसके नतीजतन लोग अपनी सुविधा से अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना व्यवसाय चला रहे हैं और सरकार इन्हें अनधिकृत करार कर रोज़गार करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। मास्टर प्लान 2011 ख़ुद मानती है कि जयपुर में असंगठित क्षेत्र में इन 10 सालों में 63% की बढ़ोत्तरी हुई है। वह यह भी मानती है कि असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परन्तु योजना में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो व्यवसायिक केन्द्र ज़रूरत के मुताबिक नहीं है दूसरी तरफ जिस तरह की परियोजना प्रस्तावित है उनसे साफ ज़ाहिर है कि योजनाकारों की नीयत क्या है?

मास्टर प्लान 2011 में प्रस्तावित आर्थिक गतिविधी केन्द्रः

- महेन्द्र सिटी (स्पेशल इकानोमिक ज़ोन)
- वर्ल्ड ट्रेड पार्क
- हाथी गांव
- फिल्म सिटी
- आई.टी.सिटी
- नोलेज कोरिडोर
- 72 कि.मी. लम्बा 3 लेन की रिंग रोड
- जेम्स और ज्वेलरी बाज़ार
- एम्यूज़मेंट पार्क
- रोप वे
- दस्तकार नगर
- मेडी टेक सिटी
- अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर
- अन्तर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स
- राजस्थान हेबीटेट सेन्टर, एन.आर.आई कालोनी
- एन.आर.आई हाऊसिंग फेज़ 2, 40,000 स्क्युएर मीटर में
- मेट्रो रेल कोरीडोर
- स्पोर्टस कोम्प्लेक्स
- गोल्डन जुबली गार्डन

स्त्रोतः मास्टर प्लान 2011

Map: proposed dev plan

उपरोक्त सभी प्रस्तावित परियोजना से स्पष्ट होता है कि सारी परियोजना मल्टीनेशनल को शहर में आकर्षित करने के लिए की जा रही हैं।

इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत तैयार 'जयपुर' शहरी विकास योजना है। विकास योजना जयपुर को आर्थिक रूप से एक वाइब्रेन्ट व उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी सुविधा वाले शहर के रूप में देखना चाहती है। परन्तु इस आर्थिक वाइब्रेन्ट शहर में गरीब मज़दूर, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की क्या स्थिति होगी, उनके लिए क्या व्यवस्था है?

जयपुर शहर विकास योजना यह चिन्हित करता है कि शहर में बेरोज़गारी बढ़ा रही है और मज़दूर हाशिये पर जी रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी बेरोज़गारी दूर करने और मुख्य धारा में लाने के कोई उपाय नहीं सुझाए गए हैं। क्या शहर का विकास केवल अभिजात्य वर्ग व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए सुविधाएं जुटाने से हो जायेगा?

इन सारी परियोजना से जयपुर एक विश्वस्तरीय शहर तो बन जाएगा पर उनमें रहने वाले मज़दूर और गरीब और बेरोज़गार होंगे। जिसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है।

❑ ❑ ❑

पारम्परिक कामों का इतिहास

जयपुर शहर देश व विदेश में अपनी कुशल व सुन्दर कारीगरी के लिए जाना जाता है। जयपुर के स्थापना से ही इसके शासकों ने कला और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया है। देश के बेहतर कारीगरों को जयपुर में आमन्त्रित किया गया। मान सिंह I ने आभूषणों में नक्काशी के लिए पंजाब से लोगों को बुलावाया और सभी प्रकार के कीमती पत्थरों को देश और विदेश से मंगवाकर, पोलिश कर देश और विदेशों में निर्यात किया जाता था।

मज़दूरों की बहुत बड़ी संख्या मन्दिर, महल, किला और छतों जैसे निर्माण कार्यों में लगी थी। इन निर्माण कार्यों ने कई कुशल और अकुशल कामगारों को रोज़गार दिया और साथ ही कई उद्योगों का भी जन्म हुआ जैसे – पत्थरों पर नक्काशी, मूर्तिकला आदि। इस प्रकार जयपुर में पत्थर नक्काशी में मूर्तिकला पुराने उद्योगों में से एक है।

जयपुर शहर में बुनाई, रंगाई, छपाई का काम मध्यकाल से चला आ रहा है। और इसलिए भी इस शहर में इन पारम्परिक कामों का अपना बाज़ार है जिसे आज भी उसी पुराने नाम से जाना जाता है:–

क्र.सं	बाज़ार का नाम	विशेष वस्तु
1.	बड़ी चौपड़	पगड़ी
2.	मीजों का रास्ता	संगमरमर की मूर्ति
3.	चमेली बाज़ार	चांदी
4.	गोपालजी का रास्ता	कीमति पत्थर
5.	हवा महल	कपड़े व ज़ेवर
6.	जौहरी बाज़ार	हर तरह के ज़ेवर
7.	कलमाज जी का रास्ता	संगमरमर की मूर्ति
8.	ख़ज़ाने वाले का रास्ता	मूर्ति, पत्थर व नक्काशी
9.	कीली बस्ती	गलीचा
10.	पनीगेरी का मोहल्ला	सोने व चांदी के वर्क
11.	सांगानेर	परम्परागत ब्लोक प्रिंटिंग
स्त्रोत : शहरी विकास योजना		

Map: traditional bazaar

❑ ❑ ❑

परम्परागत कामों की वर्तमान स्थिति

सांगानेरी छपाई, कीमति पत्थरों की कटाई व सफाई, चांदी के ज़ेवरात, मूर्ति, गलीचा व होज आबद कई ऐसे काम हैं जिससे आज भी न केवल कई लोगों को रोज़गार मिलता है बल्कि साथ में अपनी कला व संस्कृति को भी बचाए हुए हैं। ज़्यादातर परम्परागत काम पुराने शहर जिसे हम वाल्ड सिटी कहते हैं, वहां स्थित हैं और जिसे हम घरेलू उद्योग भी कहते हैं। घरेलू उद्योग में 1991 में 17,000 लोग कार्यरत थे वहीं उसकी संख्या 2001 में दुगुनी (33,000) हो गई। 1991 तक जहां उत्पादन में 12% कामगार काम करते थे वहीं उसकी संख्या 2001 में बढ़कर 15% हो गई। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल कामगार का 5% हिस्सा इस क्षेत्र में कार्यरत है।

Location Map

1. आंकड़ों का विश्लेषण

सैम्पिलिंग

परम्परागत कामों में से 9 कामों को हमने अपने सेम्पल के रूप में चुना

क्र.सं	काम	न.	प्रतिशत
1.	कीमती पत्थरों की पोलिश	59	24.08
2.	गलीचा	45	18.37
3.	बंधेज	29	11.84
4.	जरदोजी	25	10.20
5.	सांगानेरी प्रिंटिंग	25	10.20
6.	मूर्ति	22	8.98
7.	वरक	15	6.12
8.	चांदी के ज़ेवर	25	10.20
	कुल	245	100

1.1 निजी जानकारी

इस अध्ययन में कुल 245 पारमपरिक कार्य करने वाले मज़दूरों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें पुरुषों की संख्या 178 व महिलाओं की संख्या 67 है। महिलाओं की अधिकतम संख्या बंधेज व जरदोजी के कामों में से है (टेबल 1) वहीं अगर हम उनकी आयु संरचना को देखें तो पाते हैं कि 14-20 वर्ष के

18.78% मज़दूर हैं, 21-30 वर्ष के 40-82%, 31-40 वर्ष के 30.20% और 41-50 वर्ष के 8.16% हैं (टेबल 2)। 40 वर्ष के ऊपर मज़दूरें की संख्या का कम होने का एक कारण इनके रोज़गार में निहित ख़तरा है जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता भी घट जाती है।

(1) लिंग

क्र.सं	लिंग	न.	प्रतिशत
1	महिला	67	27.35
2	पुरुष	178	72.65
	कुल	245	100

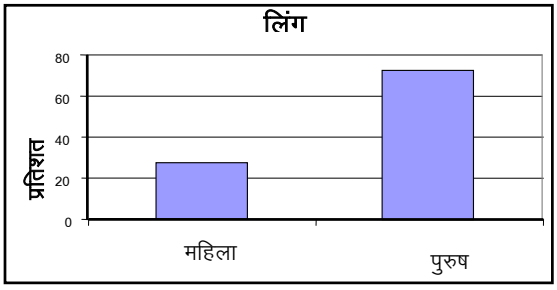

(2) कुल आयु वर्ग

क्र.सं	आयु	न.	प्रतिशत
1	14-20	46	18.78
2	21-30	100	40.82
3	31-40	74	30.20
4	41-50	20	8.16
5	50 से अधिक	4	1.63
6	कोई जवाब नहीं	1	0.41
	कुल	245	100

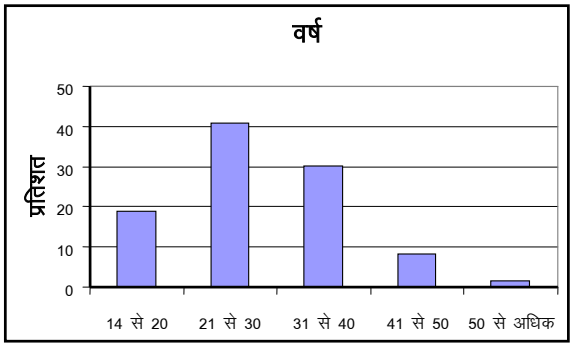

1.1.1 शिक्षा

पारम्परिक काम में कुशल कारीगर होते हैं। शायद इसलिए भी यहां अशिक्षितों (24.09%) से ज़्यादा प्राइमरी (28.16%) व उससे ज़्यादा सेकेण्डरी पढ़ें (30.20%) मज़दूरों की संख्या है(टेबल 3) ।

(3) शिक्षा

क्र.सं	शिक्षा	न.	प्रतिशत
1	अशिक्षित	60	24.49
2	प्राइमरी	69	28.16
3	सेकेण्डरी	74	30.20
4	हायर सेकेण्डरी	15	6.12
5	स्नातक	7	2.86
6	अन्य	0	0.00
7	कोई जवाब नहीं	20	8.16
	कुल	245	100

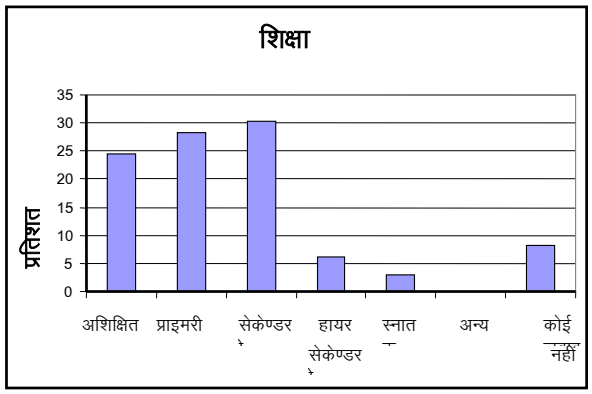

1.2 पलायन

बेहतर रोज़गार की सम्भावनाओ की तलाश में पलायन वैसे तो कोई नई प्रक्रिया नहीं है परन्तु उदारीकरण के बाद पलायन के चरित्र में बदलाव आया है (जयपुर शहर में 1991 से 2001 के बीच प्रवासियों की संख्या में 2 लाख की वृद्धि हुई। जिसमें शहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या 53.4% और गांव से आने वालों की संख्या 46.6% है)। हमारे अध्य्यन बता रहे हैं कि 45.71% कामगार 1 से 10 वर्षों व 14.29% 11 से 20 वर्ष (टेबल 4) पहले जयपुर में आये हैं। वहीं अगर हम उनके मूल स्थान पर नज़र डालें तो पाते हैं कि 63.27% (टेबल 5) कामगार राजस्थान के ही किसी हिस्से से जयपुर में आये हैं। देश के अन्य हिस्से से आए कामगार परम्परागत काम में कम लगे हैं (2001 में प्रवासियों की जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा 68% व देश के अन्य भागों का हिस्सा 32% है)

(4) **जयपुर में आगमन**

क्र.सं	वर्ष	न.	प्रतिशत
1	0-1	0	0
2	1-10	112	45.71
3	11-20	35	14.29
4	21-30	7	2.86
5	31-40	3	1.22
6	जन्म से	64	26.12
7	कोई जवाब नहीं	24	3.80
	कुल	245	100

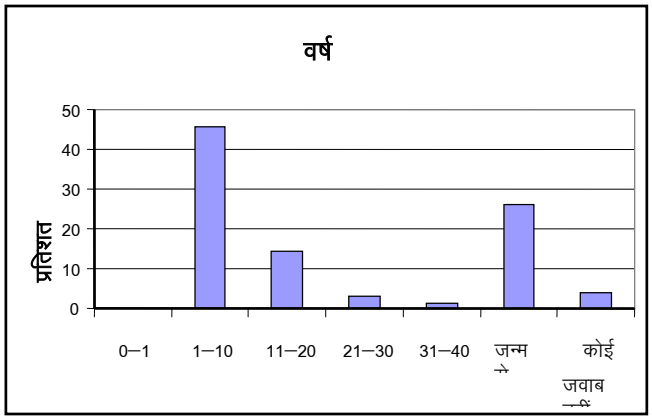

(5) **मूल स्थान**

क्र.सं	स्थान	न.	प्रतिशत
1	बिहार	2	0.82
2	जयपुर	64	26.12
3	उत्तर प्रदेश	1	0.41
4	राजस्थान	156	63.67
5	प. बन्गाल	10	4.08
6	कोई जवाब नहीं	12	4.90
	कुल	245	100

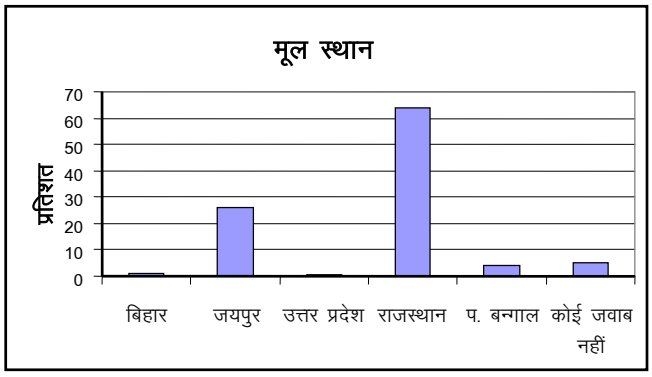

1.3 पारम्परिक काम से जुडे कामगारों का अस्थायीकरण

जयपुर में पारम्परिक कार्य मध्यकाल से चला आ रहा है। कई ऐसे समुदाय हैं जो वर्षों से परम्परागत कार्य से अपनी जीविका चला रहे हैं और इसलिए भी पूरी बस्ती का नाम उनके काम से जाना जाता है जैसे बन्धा बस्ती। परन्तु उदारीकरण के बाद रोज़गार को चलाने के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव व मुक्त बाज़ार में प्रबन्धन के ज्ञान के अभाव (Urban Informal Sector, Surjit Sinjgh IDS) के कारण लोग अपने पुश्तैनी कामों को छोड़ अन्य कामों में लग गए व उनका स्थान लिया ऐसे मज़दूरों ने जिनका वह पारम्परिक काम नहीं है। हमारे अध्य्यन बता रहे हैं कि कुल 245 सर्वेक्षण में से केवल 33 कामगारों का पारम्परिक काम है और 212 कामगारों का पारम्परिक काम नहीं है (टेबल 6)। 53.30% 1 से 5 वर्षों से, 25.94% कामगार 6 से 10 वर्षों से पारम्परिक काम कर रहे हैं (टेबल 7)। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि जब 79.34% कामगार पिछले 10 वर्षों से ही काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इन 10 सालों में पारम्परिक कामों को करने वाले मज़दूरों की संख्या बढ़ी है नतीजतन मज़दूरों की मज़दूरी घटी है (आगे के आंकड़ों से और स्पष्ट होगा)। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि अगर यह मज़दूरों का पुश्तैनी काम नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो किसी अन्य काम को छोड़ इस काम में आये हैं या धीरे–धीरे इस काम को सीखा है। हमारे अध्य्यन बता रहे हैं कि तकरीबन 55% (टेबल 8) मज़दूर एक दूसरे तरह का काम छोड़ परमपरागत काम कर रहे हैं। अर्थात इन 10-15 सालों में casual labour की संख्या बड़ी है जिसे शहर विकास योजना (जे.एन.यू.आर.एम के तहत बने) भी चिन्हित करती है।

(6) पारमपरिक काम है कि नहीं

हां	नहीं	कुल
33	212	245

(7) पारम्परिक काम कितने वर्षों से कर रहे हैं

क्र.सं	वर्ष	न.	प्रतिशत
1	1–5 वर्ष	113	53.30
2	6–10 वर्ष	55	25.94
3	11–15 वर्ष	24	11.32
4	16–20 वर्ष	12	5.66
5	21–25 वर्ष	4	1.89
6	26–30 वर्ष	2	0.94
7	30 वर्ष से ज़्यादा	1	0.47
8	कोई जवाब नहीं	1	0.47
	कुल	245	100

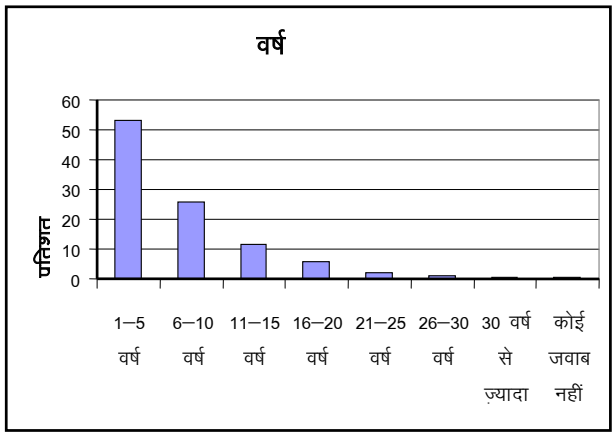

(8) परम्परागत काम से पहले का काम

क्र.सं	काम	न.	प्रतिशत
1	पहला काम	70	33.02
2	खेती	35	16.51
3	घरेलू कामकाज	11	5.19
4	अन्य मज़दूरी	45	21.23
5	अन्य काम	26	12.26
6	कोई जवाब नहीं	25	11.79
	कुल	212	100

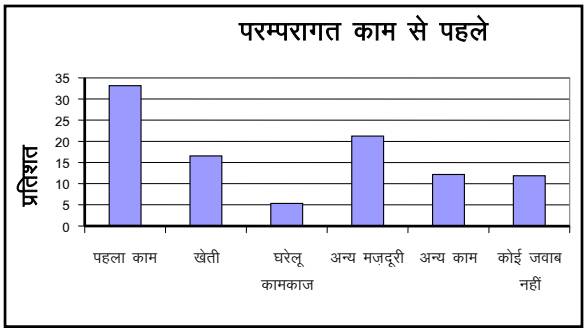

1.4 काम की प्रकृति व आर्थिक हालात

जयपुर में पारम्परिक काम को करने वाले मज़दूर स्वतंत्र रूप से भी काम करते हैं और ठेकेदार व बड़ी कम्पनी में भी काम करते हैं। हमारे अध्य्यन में 11.84% मज़दूर स्वतंत्र रूप से, 77.14% ठेकेदार के अन्तर्गत और 8.16% बड़ी कम्पनी में व 1.22% अन्य तरीके से काम करते हैं (टेबल 9)। स्वतन्त्र रूप से काम करने वाले मज़दूरें में 41.38% (टेबल 10) मज़दूर कच्चा माल बाज़ार से प्राप्त करते हैं और 51.71% ठेकेदार से प्राप्त करते हैं परन्तु केवल 20.69% (टेबल 11) ही अपना तैयार माल ख़ुद से बाज़ार में बेच पाते हैं और 68.99% (टेबल 11) ठेकेदार को बेचते हैं। यानि स्वतंत्र रूप से काम करने वाले मज़दूरों के लिए भी ठेकेदार ही बाज़ार और उनके बीच बिचौलिए काम करता है।

(9) काम की प्रकृति

क्र.सं	काम की प्रकृति	न.	प्रतिशत
1	स्वतंत्र रूप में	29	11.84
2	ठेकेदार के अन्तर्गत	189	77.14
3	बड़ी कम्पनी	20	8.16
4	अन्य काम	3	1.22
5	कोई जवाब नहीं	4	1.63
	कुल	245	100

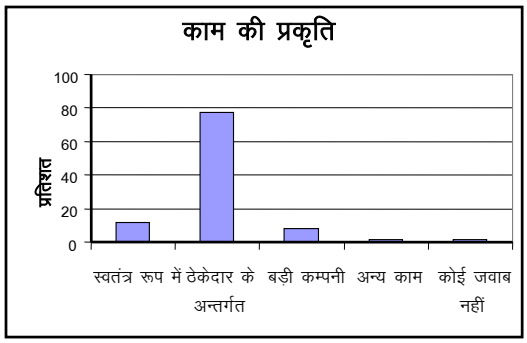

(10) कच्चे माल की स्रोत

क्र.सं	माल की स्रोत	न.	प्रतिशत
1	बाज़ार से	12	41.38
2	ठेकेदार से	15	51.71
3	अन्य	0	0
4	कोई जवाब नहीं	2	6.90
	कुल	29	100

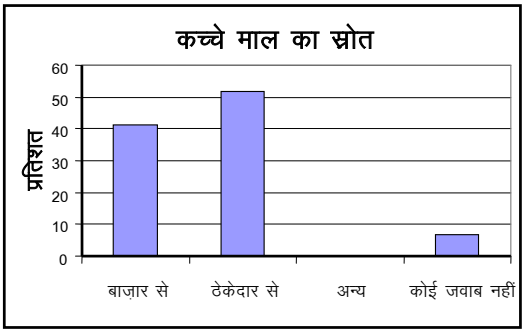

(11) तैयार माल की बिक्री

क्र.सं	तैयार माल की बिक्री	न.	प्रतिशत
1	बाज़ार में	6	20.69
2	ठेकेदार को	20	68.99
3	बड़ी कम्पनी में	0	0.00
4	अन्य	0	0
5	कोई जवाब नहीं	3	10.34
	कुल	29	100

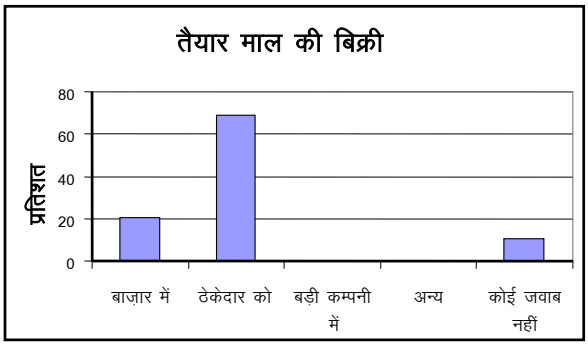

1.4.1 महीने में काम

जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है पारम्परिक कार्यों में मज़दूरों की संख्या बड़ी है (घरेलू उद्योग में 1991 में 17000 लोग कार्यरत थे वहीं उनकी संख्या 2001 में 33000 हो गई– शहर विकास योजना)। इसलिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि काम की किस किस प्रकृति की क्या अवस्था है। अध्य्यन बता रहे हैं कि पूरे महीने काम पाने वालों में स्वतंत्र रूप से काम करन वाले 58.62% मज़दूर हैं, ठेकेदार के अन्दर 40.74% हैं और 70% बड़ी कम्पनी के मज़दूर हैं। परन्तु साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि महीने में कम काम पाने वालों में ठेकेदार के अनतर्गत काम करने वाले मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है। जहां 10 दिन काम पाने वालों में 3.45% स्वतंत्र रूप से काम करते हैं वहीं 8.99% ठेकेदार के अन्दर, 15 दिन काम पाने वाले में 10.34% स्वतंत्र रूप से काम करते हैं वहीं 11.11% ठेकेदार के अन्दर, 20 दिन काम पाने वालों में 10.34% स्वतंत्र रूप से काम करते हैं वहीं 14.29% ठेकेदार के अन्दर और 25 दिन काम पाने वालों में 6.90% स्वतंत्र रूप से काम करते हैं वहीं 19.05% ठेकेदार के अन्दर व 20% बड़ी कम्पनी में। यानि ठेकेदारी कहीं न कहीं casualisation को बढ़ावा दे रहा है(टेबल 12) ।

(12) महीने में काम

	10 दिन	15 दिन	20 दिन	25 दिन	30 दिन	कोई जवाब नहीं
स्वतंत्र रूप से	1	3	3	2	17	3
प्रतिशत	3.45	10.34	10.34	6.20	58.62	10.34
ठेकेदार	17	21	27	36	77	11
प्रतिशत	8.99	11.11	14.29	19.05	40.74	5.82
बड़ी कम्पनी	0	0	0	4	14	2
प्रतिशत	0	0	0	20	70	10

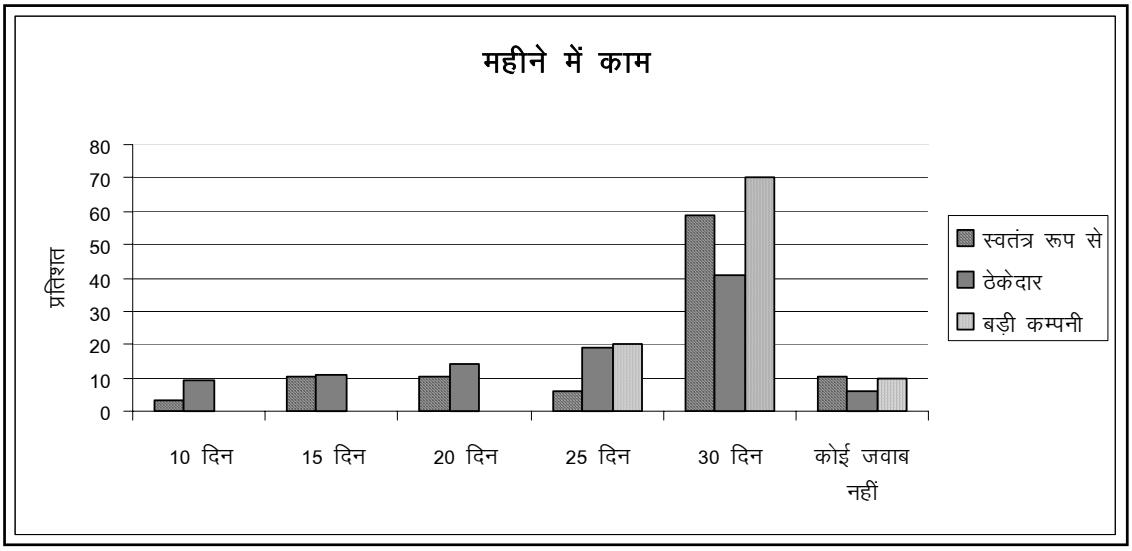

1.4.2 काम के घंटे

	8 घंटे	8–10 घंटे	10 घंटे से ज़्यादा	कोई जवाब नहीं
स्वतंत्र रूप से	11	33	10	2
प्रतिशत	**37.93**	**20..69**	**34.48**	**6.90**
ठेकेदार	33	121	29	6
प्रतिशत	**17.46**	**64.02**	**15.34**	**3.17**
बड़ी कम्पनी	3	17	0	0
प्रतिशत	**15**	**85**	**0**	**0**

टेबल 13 से स्पष्ट हो रहा है की ठेकेदार और बडी कम्पनी मे काम करने वालों के काम 8 से 10 घंटे तक नियमित है परन्तु स्वतंत्र रूप से काम करने वाले अपनी सुविधा के अनुसार या काम के अनुसार अपने घंटे तय करता हैं।

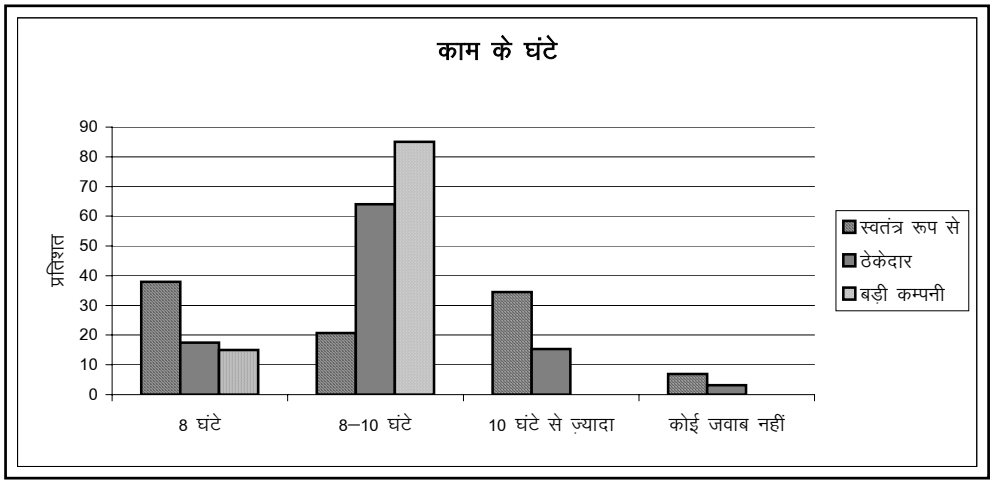

1.4.3 मज़दूरी

(14) मासिक मज़दूरी

	1000-1500	1600-2000	2100-2500	2600-3000	3100-4000	4100-4500	कोई जवाब नहीं
स्वतंत्र रूप से	2	5	3	4	0	0	0
प्रतिशत	**14.29**	**35.71**	**21.43**	**28.51**	**0**	**0**	**0**
ठेकेदार	7	66	25	12	2	1	0
प्रतिशत	**6.19**	**58.41**	**22.12**	**10.62**	**1.77**	**0.88**	**0**
बड़ी कम्पनी	0	6	10	3	0	0	1
प्रतिशत	**0**	**30**	**50**	**15**	**5**	**0**	**0.88**

(15) दिहाड़ी

	50 से कम	50-75	76-100	कोई जवाब नहीं
स्वतंत्र रूप से	11	1	2	1
प्रतिशत	**73.33**	**6.67**	**13.35**	**6.67**
ठेकेदार	42	0	20	14
प्रतिशत	**55.26**	**0**	**26.32**	**18.42**

पारम्परिक काम करने वाले अधिकतम मज़दूरेां को तुल्नात्मक रूप से महीने में पूरे दिन काम मिल जाता है परनतु अगर हम उनकी मज़दूरी की बात करें तो पाते हैं कि 1600 रु. से 2000 के बीच, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले 35.71%, ठेकेदारी के अन्दर काम करने वालों में 58.41% और 2100 रु. से 2800 रु. के बीच, स्वतंत्र रूप से काम करने वालों में 21.43% ठेकेदार के अन्दर काम करने वालो में 22.12% है वहीं 2100 रु. से 2500 रु. के बीच मासिक मज़दूरी पाने वालों में स्वतंत्र रूप से काम करने वालों में 21.43% है, ठेकेदार के अन्दर काम करने वालों में 22.12% है और 50% बड़ी कम्पनी के अन्दर काम करने वाले मज़दूर हैं। वहीं पर अगर हम दिहाड़ी की बात करें तो पाते हैं कि स्वतंत्र रूप से काम करने वालों में 73.33% व ठेकेदार के अन्दर काम करने वालों में 55.26% मज़दूरेां को 50 रु. से भी कम की मज़दूरी मिलती है। साथ ही यह भी दिख रहा है कि पारम्परिक काम के अधिकतम मज़दूरी 1600 से 2500 के बीच है और दिहाड़ी 50 रु. से भी कम। ठेकेदारी के कारण मज़दूरों की मासिक आय व दिहाड़ी न्यूनतम मज़दूरी के आस–पास या उससे कम है। वहीं हम देख़ा रहे हैं कि बड़ी कम्पनी के अन्दर काम करने वाले मज़दूरों की अधिकतम आय 2100 रु.

से 2500 रु. के बीच है। बड़ी कम्पनी जिसे हम संगठित क्षेत्र का दर्जा दे सकते हैं वहां मज़दूरों की आमदनी असंगठित क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है क्योंकि उनके बीच कोई बिचौलिनया या ठेकेदार नही होता और उन्हें निर्वाय योग्य वेतन मिल जाता है।

मज़दूर खुद बताते हैं पिछले 10 सालों में मज़दूरी काफी घटी है। जैसे बंधेज और जरदौजी के कामों में सन् 2000 तक जहां 40–50 रू मिलते थे वहीं 2006 में मज़दूरी 20–30 रु. हो गई। इसी तरह अगर हम पत्थर की पोलिशिंग की बात करें तो सन 93–95 में जहां मज़दूरी 1800 रु. मिलती थी वहीं 1999–2000 में बढ़कर 4500 और 2006 में घटकर 2800 रु. हो गई है।

ठेकेदारी प्रथा की सबसे बड़ी मार मज़दूर, मज़दूरी समय पर न मिलने के रूप में झेलते हैं। एक तो कम होती मज़दूरी और वो भी अगर समय पर न मिले तो मज़दूर अपनी जीविका कैसे चलाते हैं?

(16) मज़दूरी न मिलने के दौरान जीविका

क्र.सं	क्या करते हैं	न.	प्रतिशत
1	बचत से	4	1.63
2	उधार लेकर	237	96.73
3	अन्य	1	0.41
4	कोई जवाब नहीं	3	1.22

96.73 मज़दूर अपनी जीविका उधार लेकर ही चलाते हैं।

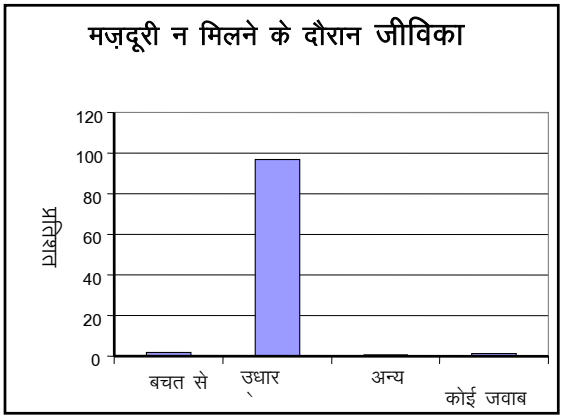

(17) उधार किनसे लेते हैं

क्र.सं	उधार लेते हैं	न.	प्रतिशत
1	महाजन से	81	34.18
2	रिश्तेदार से	61	25.74
3	अन्य से	90	37.97
4	कोई जवाब नहीं	5	2.1

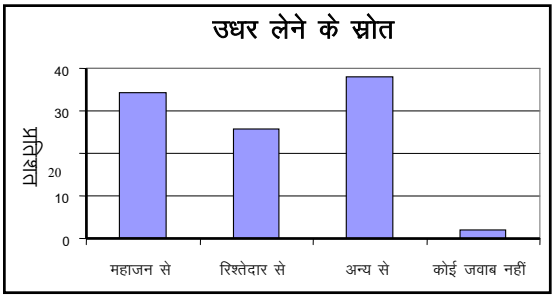

मज़दूर अपने–अपने स्त्रो से उधार ले कर अपना काम चलाते हैं। 34.18% मज़दूर महाजन से उधार लेते हैं। 25.74% मज़दूर रिश्तेदार से उधार लेते हैं और 37.97% मज़दूर अन्य अर्थात अपने दोस्तों व जान–पहचान वालों से उधार ले कर अपनी जीविका चलाते हैं।

1.5. आवास एवं अन्य सुविधाएं

(18) शहर में आवास

क्र.सं	आवास	न.	प्रतिशत
1	झुग्गी	1	0.41
2	कच्ची कालोनी	57	23.27
3	पक्की कालोनी	177	72.24
4	पुनर्वास	0	0
5	अन्य	3	1.22
6	कोई जवाब नहीं	7	2.86

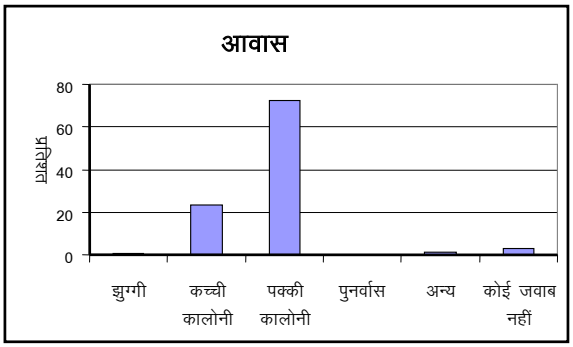

(19) घर के प्रकार

क्र.सं	प्रकार	न.	प्रतिशत
1	कच्चा	50	20.41
2	पक्का	182	74.29
3	कोई जवाब नहीं	13	5.31

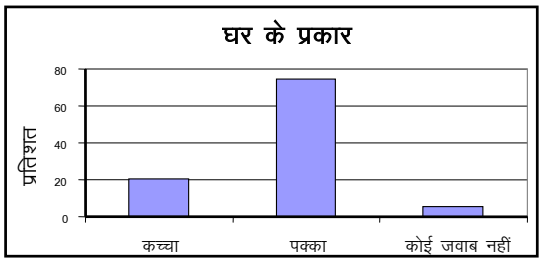

23-27% मज़दूर कच्ची कालोनियों में रहते हैं वहीं 72.24% मज़दूर पक्की कालोनियों में रहते हैं। साथ ही 20.41% मज़दूर कच्चे मकानों व 74.29% मज़दूर पक्के मकानों में रहते हैं।

(20) मिलकियत

क्र.सं	मिलकियत	न.	प्रतिशत
1	ख़ुद का	126	51.43
2	किराये का	110	44.90
3	अन्य	2	0.82
4	कोई जवाब नहीं	7	2.86

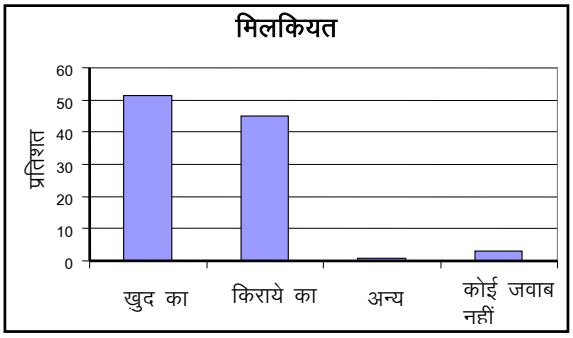

1.43% मज़दूरों का ख़ुद का मकान है वहीं पर 44.90% मज़दूर किराये के मकान में रहते हैं।

कच्ची और पक्की कालोनियों में अगर हम मिलकियत और घर के प्रकार के आंकडों को देखें तो पाते हैं कि :–

(21) कच्ची कालोनियों में

	ख़ुद का	किराए का	अन्य	कोई जवाब नहीं
कच्चे घर	38	7	0	1
प्रतिशत	**82.61**	**15.22**	**0**	**2.17**
पक्के घर	6	0	0	0
प्रतिशत	**100**	**0**	**0**	**0**

(22) पक्की कालोनियों में

	ख़ुद का	किराए का	अन्य	कोई जवाब नहीं
कच्चे घर	1	2	0	0
प्रतिशत	33.33	66.67	0	0
पक्के घर	72	98	0	1
प्रतिशत	42.11	57.31	0	0.58

कच्ची कालोनी में जहां दोनों ही प्रकार (कच्चे व पक्के) के घर अधिकतम लोगों के अपने हैं वहीं पक्की कालोनी में चाहे वे कच्चे धर हो या पक्के अधिकतम मज़दूर (66.67%) आर 57.31 मज़दूर किराए पर रहते हैं।

(23) पानी के स्त्रोत

क्र.सं	स्त्रोत	न.	प्रतिशत
1	हैण्ड पम्प	33	13.47
2	टैप	186	75.92
3	कुआं	12	4.90
4	अन्य	2	0.82
5	हैण्ड पम्प एवं टैप	4	1.63
6	कोई जवाब नहीं	8	3.27

75.92% मज़दूरों के पानी का स्त्रोत सरकारी टैप है और 13.47% मज़दूर हैण्ड पम्प का इस्तेमाल करते हैं।

(24) शौचालय

क्र.सं	शौचालय	न.	प्रतिशत
1	ख़ुद का	107	43.67
2	सार्वजनिक	80	32.65
3	खुले में	53	21.63
4	कोई जवाब नहीं	5	2.04

1.6 मज़दूरों की सबसे बड़ी परेशानी

जब यह जानने की कोशिश की गई कि मज़दूर खुद सबसे बड़ी परेशानी किसे मानते हैं। उनका जवाब था :–

(25) परेशानी

क्र.सं	परेशानी	न.	प्रतिशत
1	कम मज़दूरी	114	46.53
2	पक्का काम न होना	23	9.39
3	कम काम मिलना	74	30.20
4	काम का अस्वस्थ माहौल	17	6.94
5	कोई जवाब नहीं	17	6.94

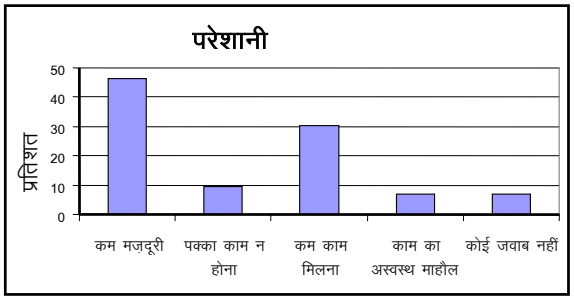

46.53% मज़दूरों की परेशानी कम मज़दूरी है। 9.39% मज़दूरों की सबसे बड़ी परेशानी पक्का काम न होना और 30.20% मज़दूरेां की परेशानी कम काम मिलना और 6.94% मज़दूरेां की परेशानी काम का अस्वस्थ माहौल है।

❑ ❑ ❑

शहर की योजना में पारम्परिक काम करने वाले मज़दूर का स्थान

पारम्परिक काम करने वाले मज़दूर न केवल इन कामों से अपनी जीविका चला रहे हैं बल्कि जयपुर शहर की उस परम्परा को भी जीवित रखे हुए हैं जिसक सहारा ले कर राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और साथ ही उससे आमदनी भी कमा रही है। यानि पारम्परिक काम करने वाले मज़दूर जयपुर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे शहर का मास्टर प्लान और शहर विकास योजना भी मानती है। किन्तु प्रस्तावित आर्थिक गतिविधि केन्द्र (पेज 7) में जेम्स और ज्वेलेरी बाज़ार और दस्तकार नगर जैसी परियोजना पारम्परिक कामों को तथाकथित रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित है किन्तु जैसा कि उपरोक्त आंकड़े में भी दिख रहा है कि काम मिलना कम नहीं हुआ है बल्कि मज़दूरी की दर दिन–पे–दिन घटती जा रही है। इसलिए यह ज़रूरी है कि शहर की योजना में इन मज़दूरों को प्रस्तावित परियोजना में जगह मिलने के साथ–साथ काम की गारंटी भी मिलनी चाहिए। मज़दूरों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए आवश्यकता है कि उन्हें ठेकेदारी प्रथा के चंगुल से बचाया जाए। जिसके लिए आवश्यक है कि उन्हें स्व–रोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसके लिए ज़रूरी हर सुविधा–प्रशिक्षण, लोन की व्यवस्था, व्यवसाय करने के लिए उचित स्थान व संसाधन मुहैय्या करवाये जाएं। तभी जयपुर अपनी परम्परा को भी बचाये रख सकता है।

❑ ❑ ❑

निष्कर्ष

उदारीकरण के 15–16 सालों में मज़दूरों को लेकर सरकार की कोशिश तथा मज़दूरों की दशा की उभरती तस्वीरें को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आ रही हैं:–

उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद गांव, छोटे शहर, मझोले शहर, बड़े शहर में बदल रहे है व बड़े शहर और भी बड़े हो रहे हैं और साथ ही देख रहे हैं कि सारी आर्थिक गतिविधियां का केन्द्र शहर ही बनता जा रहा है। इस बढ़ते पलायन के नतीजतन एक तरफ मज़दूरेां की एक रिज़र्व सेना तैयार हो रही है व दूसरी तरफ प्रति इकाई पूंजी पर रोज़गार कम हो रहा है। इस बढ़ते रिज़र्व सेना के श्रम शक्ति का दोहन पूंजीपति वर्ग अपने फायदे के लिए बखूबी कर रही है – रोज़गार में स्वामित्व नहीं है और मज़दूरों की काम बदल–बदल कर करने की प्रवृति भी बढ़ रही है। उपरोक्त आंकड़ें से यह स्पष्ट हो रहा है कि मज़दूर ठेकेदारों के चंगुल में हैं। इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। मज़दूरों की मज़दूरी दिन–ब–दिन गिरती जा रही है। मज़दूरी कम मिलने के नतीजतन एक मज़दूर लगातार एक तरह के कर्जे में डूबे रहते हैं।

बढ़ती मज़दूरों की रिज़र्व सेना, घटते रोज़गार व मशीनीकरण का एक और प्रभाव देख रहे हैं कि मज़दूरों की सामूहिक सौदा करने की ताकत भी ख़त्म हो रही है।

और अन्त में इतना ही कहा जा सकता है कि जब मज़दूरों की सबसे बड़ी परेशानी कम मज़दूरी है तो निश्चित तौर पर योजनाकारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ मज़दूरों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए उपाए ढूंढने होंगे और देश के ट्रेड यूनियनों को भी उनके सामूहिक सौदा करने की ताकत का अहसास करवाना पड़ेगा तभी वे सामूहिक रूप से अपने हकों की मांग कर सकते हैं।

❑ ❑ ❑

For further details, please contact:
Hazards Centre
92 H Pratap Market
Munirka
New Delhi 110067
011-26187896, 26714244
haz_cen@vsnl.net

Cover page by Vinod Koshti